

राज्य लोक सेवा आयोगों (PSCs) में सुधार

जीएस-2: सरकारी नीतियाँ, शासन के मुद्दे, भारत में सिविल सेवाएँ

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना पीएससी द्वारा आयोजित राज्य पीएससी अध्यक्षों का 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन 19-20 दिसंबर को होने जा रहा है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य पीएससी पेपर लीक, देरी, मुकदमेबाजी, अपारदर्शी कामकाज और घटती विश्वसनीयता को लेकर बढ़ती आलोचना का सामना कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थी अक्सर राहत के लिए अदालतों का रुख करते हैं, जिससे विश्वास की कमी बढ़ रही है।

इसलिए, यह सम्मेलन राज्य पीएससी के कामकाज में संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और संवैधानिक चुनौतियों का पुनर्मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पीएससी का विकास

मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधारों की भूमिका

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, राष्ट्रवादी नेताओं ने सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए योग्यता-आधारित प्रवेश की मांग की थी। मोंटागु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918) ने इस सिद्धांत का समर्थन किया और सिविल सेवा भर्ती के लिए एक स्थायी, राजनीतिक रूप से अलग प्राधिकरण की सिफारिश की।

परिणामस्वरूप:

- 1926: संघ के लिए भारत के पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना¹
- 1935: भारत सरकार अधिनियम में प्रत्येक प्रांत में एक पीएससी का प्रावधान किया गया²

ये प्रावधान संविधान में बनाए रखे गए, जिससे यूपीएससी + राज्य पीएससी की संघीय भर्ती संरचना (अनुच्छेद 315-323) का उदय हुआ। इस प्रकार, वर्तमान पीएससी प्रणाली भारत में ब्रिटिश संवैधानिक विकास की एक सीधी संस्थागत विरासत है।



Montagu Chelmsford Reforms

लोक सेवा आयोग क्या हैं?

लोक सेवा आयोग (PSCs) संवैधानिक निकाय हैं जो भारत में सिविल सेवाओं में निष्पक्ष, योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। अनुच्छेद 312 के तहत, संसद अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है, जिसके लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाती है।

इसी तरह, प्रत्येक राज्य अपने प्रशासनिक सेवाओं के लिए अपने राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के माध्यम से भर्ती करता है।

यूपीएससी और एसपीएससी दोनों अपनी शक्तियाँ अनुच्छेद 315-323 से प्राप्त करते हैं, जो निम्नलिखित का प्रावधान करते हैं:

- पीएससी की स्थापना (अनुच्छेद 315)
- सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और हटाना (अनुच्छेद 316-317)

- नियम बनाने की शक्तियाँ (अनुच्छेद 318)
- कार्यात्मक जिम्मेदारियाँ (अनुच्छेद 320)
- वार्षिक रिपोर्टिंग (अनुच्छेद 323)
- समेकित निधियों के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता।

संरचना और कार्यकाल

विशेषता	यूपीएससी (UPSC)	राज्य पीएससी (State PSCs)
नियुक्ति	राष्ट्रपति द्वारा	राज्यपाल द्वारा
कार्यकाल	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक	6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
हटाना	केवल राष्ट्रपति द्वारा	केवल राष्ट्रपति द्वारा
व्यय भार	भारत की समेकित निधि पर भारित	राज्य की समेकित निधि पर भारित

कार्यकाल के बाद प्रतिबंध

- **यूपीएससी अध्यक्ष:** आने किसी भी सरकारी रोजगार के लिए पात्र नहीं।
- **यूपीएससी सदस्य:**
यूपीएससी/एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं।
- **एसपीएससी अध्यक्ष/सदस्य:**
यूपीएससी/एसपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए पात्र।

इस संवैधानिक संरचना का उद्देश्य सार्वजनिक भर्ती में स्वतंत्रता, तटस्थता और निष्पक्षता को बनाए रखना है।



संरचनात्मक अंतर: यूपीएससी बनाम राज्य पीएससी

@resultmitra | www.resultmitra.com | 9235313184, 9235440806

विशेषता	यूपीएससी (UPSC): राजनीतिक रूप से तटस्थ और सु-संसाधित	राज्य पीएससी (State PSCs): राजनीतिक रूप से प्रभावित और संसाधन-सीमित
सदस्यों का चयन	योग्यता, अनुभव पर चयनित; आमतौर पर 55+	नियुक्तियाँ राजनीतिक संरक्षण से प्रभावित।
प्रतिनिधित्व	विविध क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व।	कोई समान योग्यता मानदंड नहीं।
संसाधन	पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन।	अनियमित रिक्रिट घोषणाएँ।
क्षमता	समर्पित कार्मिक मंत्रालय (DoPT) द्वारा समर्थित।	कमजोर प्रशासनिक क्षमता $\rightarrow$ देरी + मुकदमेबाजी।
समयबद्धता	समय पर अधिसूचनाएँ, परीक्षाएँ और परिणाम।	अक्सर देरी होती है और मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है।

कार्यात्मक अंतर: यूपीएससी बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है

कारक	यूपीएससी (UPSC)	राज्य पीएससी (State PSCs)
पाठ्यक्रम	विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से नियमित पाठ्यक्रम संशोधन।	शायद ही कभी पाठ्यक्रम अद्यतन किए जाते हैं।
प्रश्न-पत्र	प्रश्न-निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा तक पहुँचा।	प्रश्न-निर्माण के लिए सीमित प्रतिभा पूल।
मूल्यांकन	मज़बूत मॉडरेशन (Moderation) प्रथाएँ।	लगातार आरक्षण-संबंधी विवाद।
पारदर्शिता	पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच बेहतर संतुलन।	अनुवाद त्रुटियाँ, मॉडरेशन विफलताएँ।
तकनीक	उन्नत डिजिटल बुनियादी ढाँचा।	कमजोर डिजिटल बुनियादी ढाँचा \$\\rightarrow\$ लीक और अदालती मामले।

DoPT की भूमिका: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

DoPT केंद्रीय कार्मिक प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो निम्नलिखित को संभालता है:

- सिविल सेवा भर्ती नीति
- प्रशिक्षण (LBSNAA, SSC, UPSC)
- सतर्कता, सेवा शर्तें
- पेंशन सुधार और शिकायत निवारण

इसका अस्तित्व पूर्वानुमेयता और व्यावसायिकता प्रदान करता है, जिसकी कमी अधिकांश राज्यों में है क्योंकि उनके पास समकक्ष राज्य-स्तरीय कार्मिक मंत्रालय नहीं हैं।

क्या पाठ्यक्रम की आवधिक समीक्षा आवश्यक है?

हाँ — बिल्कुल।

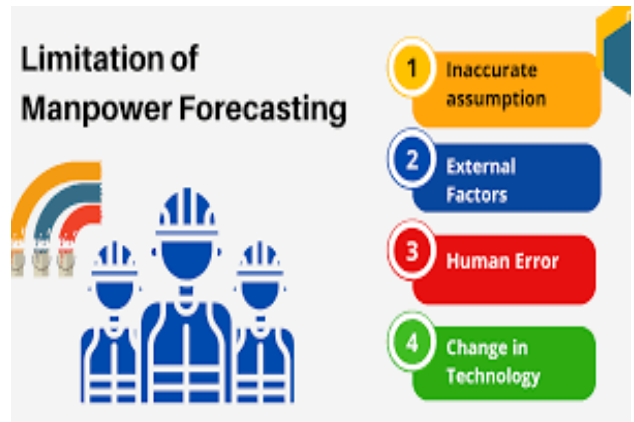
क्यों?

- शासन की चुनौतियाँ तेज़ी से विकसित हो रही हैं।
- यह प्रशासनिक आवश्यकताओं और परीक्षा सामग्री के बीच बेमेल को रोकता है।
- प्रश्न पैटर्न में पूर्वानुमेयता को कम करता है।
- एआई-जनित उत्तरों के दुरुपयोग का मुकाबला करने में मदद करता है।
- यूपीएससी के आवधिक अपडेट निष्पक्षता + प्रासंगिकता सुनिश्चित करते हैं, जो अनुकरण करने योग्य एक मॉडल है।

राज्य पीएससी के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं?

1. एक समर्पित राज्य कार्मिक मंत्रालय का निर्माण

- जनशक्ति का पूर्वानुमान (Manpower forecasting)
- पाँच वर्षीय भर्ती कैलेंडर
- नियमित रिक्ति अधिसूचनाएँ
- विभागों और पीएससी के बीच समन्वय



2. नियुक्ति मानदंडों के लिए संवैधानिक संशोधन

निम्नलिखित के लिए समान मानक तय करना:

- न्यूनतम आयु: 55 वर्ष, अधिकतम: 65 वर्ष।
- अनिवार्य योग्यताएँ:
 - आधिकारिक सदस्य: राज्य सरकार के सचिव के रूप में सेवा की हो।
 - गैर-आधिकारिक सदस्य: कम से कम 10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।
- द्विदलीय प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति $\rightarrow$ विपक्ष के नेता के साथ परामर्श। यह क्षमता सुनिश्चित करता है + राजनीतिकरण को कम करता है।

3. सार्वजनिक परामर्श के साथ नियमित पाठ्यक्रम संशोधन

- यूपीएससी-शैली में विशेषज्ञ समिति की समीक्षा।
- सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए पाठ्यक्रम का मसौदा प्रकाशित करना।
- राज्य-विशिष्ट विषयों को वस्तुनिष्ठ रूप से शामिल करना।
- हाइब्रिड मुख्य परीक्षा पैटर्न: वस्तुनिष्ठ + व्यक्तिपरक (Objective + Subjective)।
- अनुवाद के लिए एआई + मानव निरीक्षण का उपयोग।
- एआई-प्रेरित कदाचार को रोकने के लिए पैटर्न को घुमाना (Rotate)।

4. प्रशासनिक क्षमता को मज़बूत करना

- परीक्षा प्रशासन में अनुभव वाले पीएससी सचिवों की नियुक्ति।
- यूपीएससी-शैली के मॉडरेशन + गोपनीयता मानदंडों को अपनाना।
- मज़बूत डिजिटल परीक्षा प्रणालियों में निवेश करना।
- लीक को रोकने के लिए एन्क्रिप्शन, बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करना।

निष्कर्ष

राज्य पीएससी भारत की संघीय कार्मिक संरचना के आवश्यक स्तंभ हैं। हालांकि, बढ़ती चुनौतियों—परीक्षा लीक, मुकदमेबाजी, अनियमित अधिसूचनाएँ, कमजोर मॉडरेशन और राजनीतिक नियुक्तियों—ने जनता के विश्वास को कम कर दिया है।

प्रणालीगत जनशक्ति नियोजन, द्विदलीय नियुक्तियों, नियमित पाठ्यक्रम अपडेट, आधुनिक परीक्षा प्रणालियों और बेहतर प्रशासनिक क्षमता के साथ, राज्य पीएससी यूपीएससी के बराबर विश्वसनीयता और व्यावसायिकता हासिल कर सकते हैं।

एक सुधारित, पारदर्शी और जवाबदेह पीएससी पारिस्थितिकी तंत्र भारत के राज्यों में योग्यता, दक्षता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न-

प्र 1. भारत में लोक सेवा आयोगों (PSCs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान अनुच्छेद 315 के तहत संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग अनिवार्य करता है।
2. राज्य PSC के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है।
3. राज्य PSC के खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3



प्र 2. UPSC और राज्य PSC के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए:

1. UPSC को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से निरंतर नीतिगत समर्थन प्राप्त होता है, जबकि अधिकांश राज्यों में एक समर्पित कार्मिक मंत्रालय का अभाव है।
2. UPSC सदस्यों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता तय है, लेकिन राज्य PSC सदस्यों के लिए नहीं।
3. UPSC के पाठ्यक्रम को विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, जबकि अधिकांश राज्य PSC के पाठ्यक्रम लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्र 3. PSC से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के तहत:

1. राष्ट्रपति UPSC सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्णय करते हैं।
2. राज्यपाल राज्य PSC सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्णय करते हैं।
3. UPSC अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद आगे किसी भी सरकारी रोजगार के लिए पात्र होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्र 4. भारत में PSC के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) भारत में पहला लोक सेवा आयोग भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बाद स्थापित किया गया था।
- (b) मोंटगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने एक राजनीतिक रूप से अलग (insulated) सिविल सेवा भर्ती निकाय की सिफारिश की थी।
- (c) प्रांतीय PSC केवल स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे।
- (d) संविधान ने औपनिवेशिक काल के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ के बिना PSC का निर्माण किया।

प्र 5. राज्य PSC में पाठ्यक्रम और परीक्षा सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाइब्रिड मुख्य परीक्षा प्रारूप (वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक) मूल्यांकन पूर्वाग्रह को कम कर सकता है।

2. मसौदा पाठ्यक्रम पर सार्वजनिक परामर्श संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
3. AI-आधारित अनुवाद उपकरण बहुभाषी प्रश्नपत्रों में त्रुटियों को कम करने में मदद कर सकते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

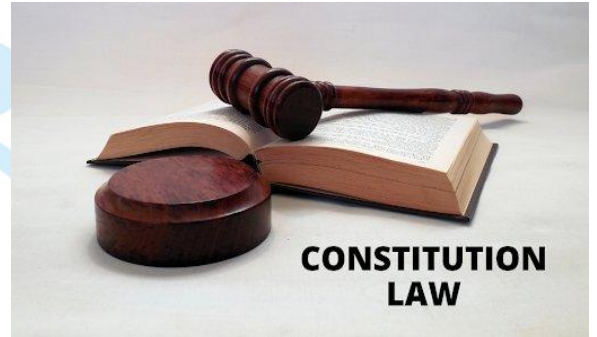
- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

प्र 6. अनुच्छेद 320 के तहत लोक सेवा आयोगों के कार्य निम्नलिखित में से कौन-से हैं?

- 1. परीक्षाओं के माध्यम से सेवाओं के लिए भर्ती
- 2. अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना
- 3. अंतर-राज्य कैडर स्थानान्तरण का प्रबंधन
- 4. पदोन्नति पर सलाह देना

सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4



प्र 7. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

- 1. राज्य PSC सदस्यों के लिए निश्चित योग्यता और न्यूनतम आयु मानदंड
- 2. नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष के नेता की अनिवार्य भूमिका
- 3. एक समर्पित राज्य कार्मिक मंत्रालय की स्थापना
- 4. वार्षिक भर्ती कैलेंडर और जनशक्ति पूर्वानुमान

उपरोक्त में से कौन-सा/से राज्य PSC के कामकाज में सुधार के लिए प्रस्तावित सुधार है/हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्र 8. "Inter-se Moderation", जिसका उपयोग अक्सर UPSC द्वारा किया जाता है, का तात्पर्य है:

- (a) वर्णनात्मक उत्तरों के मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता को कम करने की एक विधि
- (b) श्रेणियों के बीच अंकों को वितरित करने की आरक्षण-आधारित विधि
- (c) बहुभाषी परीक्षाओं के लिए अनुवाद सत्यापन तकनीक
- (d) एक मॉडरेशन तकनीक जिसका उपयोग केवल वैकल्पिक विषयों के लिए किया जाता है।

प्र 9. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएं PSC की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं?

- 1. सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाना
- 2. नियुक्ति के बाद सदस्यों की सेवा शर्तों को उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है

3. व्यय संचित निधि पर भारित होते हैं
4. छह वर्ष का निश्चित कार्यकाल

सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्र 10. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

प्रस्तावित सुधार	उद्देश्य
1. प्रश्न पैटर्न को घुमाना	पूर्वानुमेयता को रोकना
2. बायोमेट्रिक सत्यापन	प्रतिरूपण को कम करना
3. राज्य-विशिष्ट विषयों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रारूप	मूल्यांकन पूर्वाग्रह को कम करना

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित हैं/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Answers

1. (b)
2. (b)
3. (b)
4. (b)
5. (b)
6. (b)
7. (d)
8. (a)
9. (b)
10. (d)

resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

